राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 230/2016

तन्मय पाठक पुत्र श्री रमेश चंद पाठक, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य लोक अभियोजक के माध्यम से।
2. श्रीपाल जैन पुत्र देव चंद जैन, निवासी 3/63, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	डॉ. सचिन आचार्य, श्री राहुल राजपुरोहित की सहायता से।
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री मृदुल जैन श्री के.सी. शर्मा श्री विक्रम राजपुरोहित, उप.शा.अ. श्री रवीन्द्र सिंह, स.लो.अ.

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>11/02/2025</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह तत्काल विविध याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी संख्या 35/2016 को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक शिकायत दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत अपराध किए हैं। उसने दावा किया कि उसने याचिकाकर्ता और उसके दिवंगत

भाई, कौशल पाठक से दिनांक 10.07.2012 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 35 लाख रुपये में मोहन कॉलोनी, घाटोल रोड, बांसवाड़ा में 28.6x70 वर्ग फीट (कुल 1995 वर्ग फीट) माप की एक संपत्ति, एक निर्मित मकान के साथ खरीदी थी। उसने आगे कहा कि साक्षियों की उपस्थिति में उसे कब्ज़ा सौंप दिया गया था। हालांकि, कथित तौर पर याचिकाकर्ता ने झूठे बहाने से संपत्ति में पुनः प्रवेश किया, जबकि विक्रय विलेख में पूर्ण भुगतान और कब्ज़े की पुष्टि की गई थी। इस कारण से, शिकायतकर्ता ने एक प्राथमिकी दायर की।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 या 406 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि कब्ज़ा शिकायतकर्ता की सहमति से रखा गया था और जबरन नहीं लिया गया था। उसने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के दिवंगत भाई की विधवा के माध्यम से संपत्ति के एक आसन्न लेकिन अविभाजित हिस्से के लिए अपने पक्ष में एक और विक्रय विलेख निष्पादित कराया। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सिविल वाद पहले से ही लंबित है, जिसमें कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी अनुचित दबाव बनाने का एक प्रयास है, जिससे उसके पास इसे रद्द करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है, क्योंकि शिकायतकर्ता पहले ही सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद दायर कर चुका है। याचिकाकर्ता ने आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। विशेष रूप से, शिकायतकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी, और इसके बाद ही, शिकायतकर्ता ने वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने का सहारा लिया। यह कृत्य एक सिविल विवाद को आपराधिक अपराध का रंग देने का प्रयास दर्शाता है, जो कानून में अनुमेय नहीं है। केवल अनुबंध के उल्लंघन के आरोप आपराधिक अपराध का गठन नहीं करते हैं, और शिकायतकर्ता के लिए उचित उपचार सिविल कार्यवाही में निहित है, न कि आपराधिक मामले में। इसलिए, प्राथमिकी की निराधार और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को देखते हुए, न्याय के हित में इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया है। विद्वान लोक अभियोजक ने इस न्यायालय के अवलोकन के लिए दिनांक 03.01.2018 की तथ्यात्मक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया और आक्षेपित प्राथमिकी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. रिकॉर्ड का अवलोकन करने और न्यायालय को उपलब्ध कराए गए तर्कों और सामग्री पर विचार करने के बाद, प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि मामला याचिकाकर्ता और उसके भाई से शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए एक प्लॉट से संबंधित विवाद से संबंधित है। हालांकि, जिसका कब्ज़ा अभी भी याचिकाकर्ता के पास था और वह न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी वहीं रह रहा था। शिकायतकर्ता ने यह याचिका इसलिए दायर की क्योंकि याचिकाकर्ता ने संपत्ति में प्रवेश किया और उस भूमि के कब्ज़े का दावा कर रहा है।

7. यहां, इस न्यायालय के समक्ष निर्णयन के लिए यह प्रश्न आता है कि क्या प्राथमिकी में शिकायतकर्ता द्वारा कथित कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर इस न्यायालय को विचार करना है और उपरोक्त आधार पर, प्राथमिकी को रद्द करने और जांच को रोकने के लिए एक याचिका बनाए रखी जा सकती है या नहीं, इसकी जांच की जानी है।

8. यह न्यायालय महसूस करता है कि न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए हैं और केवल इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं। अपनी स्थापना के पहले दिन से, यह न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों को प्राप्त करता है और रखता है और इस प्रकार न्याय के वितरण के उद्देश्य के लिए, यह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत व्यक्त प्रावधान केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए और साथ ही कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या विफल करने के उद्देश्य के लिए न्यायालयों में अंतर्निहित और समाहित हैं। क्या उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति में, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है, एक आपराधिक शिकायत या एक प्राथमिकी को रद्द कर सकता है, इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौधरी भजन लाल और अन्य, रिपोर्टेड ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 604** के मामले में बहुत विस्तृत और बुद्धिमानी से प्रतिपादित किया गया है, माननीय उच्चतम

न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित मुद्दे के कैनवास को विस्तार से समझाया है। आसान संदर्भ के लिए, निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> 105...अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुन: प्रस्तुत किया है के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से संरेखित और कड़े दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और उन असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
>
> I. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके मुख मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।
>
> II. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्राथमिकी के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को न्यायोचित ठहराने वाला कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करती है, सिवाय संहिता की धारा 155(2) के दायरे में एक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत।
>
> III. जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अविवादास्पद आरोप और इसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के कारित होने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।
>
> IV. जहां, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित एक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच अनुमत नहीं है।
>
> V. जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभव हैं कि जिसके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी एक न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।
>
> VI. जहां संहिता के किसी भी प्रावधान या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) में कार्यवाही की स्थापना और निरंतरता के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो व्यथित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

VII. जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से जुड़ी हुई है और/या जहां निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त मकसद से और उसे परेशान करने की दृष्टि से कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्थापित की गई है।

विचाराधीन मामला **भजन लाल (उपरोक्त)** में उल्लिखित पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवीं श्रेणी के अंतर्गत आता है जहां यह कहा गया है कि प्राथमिकी में उल्लिखित आरोप प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनाते हैं या गठित नहीं करते हैं, प्राथमिकी और प्राथमिकी के साथ संलग्न अन्य सामग्री में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करते हैं, प्राथमिकी में लगाए गए अविवादास्पद आरोप और इसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के कारित होने का खुलासा नहीं करते हैं और अंत में, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभव हैं कि जिसके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी एक न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। रद्द करने की शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

9. सबसे पहले, इस न्यायालय को यह जांचना होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध बनता है या नहीं। आसान संदर्भ के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 को इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

धारा 406 भा.दं.सं.: आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड।

जो कोई भी आपराधिक विश्वासघात करेगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

प्रावधान का अवलोकन दर्शाता है कि आपराधिक विश्वासघात के अपराध को स्थापित करने के लिए, कुछ प्रमुख तत्वों का उपस्थित होना आवश्यक है जिसमें शामिल हैं: (क) सुपुर्दगी का तथ्य, (ख) बेईमान इरादा और (ग) खुद के उपयोग के लिए संपत्ति का गबन या परिवर्तन या संपत्ति का निपटान।

10. **अभिषेक सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3628/2023, निर्णय दिनांक: 28.11.2023** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तत्वों या

अनिवार्यताओं को बताया था जो आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए अनिवार्य तत्व इस प्रकार हैं-

i. संपत्ति का या उस संपत्ति पर अधिकार का न्यास होना चाहिए जिसके विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं।

ii. व्यक्ति ने बेईमानी से उस व्यक्ति को सौंपी गई कर्तव्यों के उल्लंघन में संपत्ति का दुरुपयोग किया और उसे गबन किया या अपने उपयोग के लिए परिवर्तितकर लिया।

iii. व्यक्ति ने कानून के किसी भी निर्देश के उल्लंघन में संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान किया जो उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है।

iv. अंत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तत्वों का उल्लंघन होना चाहिए।

यह उल्लेख किया गया है कि न्यास और बेईमानी से उपयोग या किसी भी संपत्ति के निपटान के इन बुनियादी तत्वों की अनुपस्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 का अपराध आकर्षित नहीं होगा।

11. **गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नथालाल, रिपोर्टेड ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 700** के मामले में, "न्यास" के अर्थ को समझाया गया है कि जिस व्यक्ति ने कोई संपत्ति हस्तांतरित की थी या उनकी ओर से हस्तांतरित करता है , वह भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अनुसार उस संपत्ति का मालिक बना रहता है।

12. **उषा चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,** रिपोर्टेड **ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 688** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से उन सभी अनिवार्यताओं पर विचार किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आरोप लगाने के लिए उपस्थित होनी चाहिए।

13. यह समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को संपत्ति का न्यास भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध गठित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है।

उक्त धारा आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड खंड की परिकल्पना करती है, जिसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत प्रावधान का एक साधारण पठन यह प्रकट करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति, चल या अचल, के कब्ज़े को किसी को हस्तांतरित करने के लिए किसी पर अपना विश्वास रखता है, और वह व्यक्ति संपत्ति को अपने पास रखकर उस विश्वास का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के दायरे में आएगा। संपत्ति के न्यास के अलावा, व्यक्ति ने उस व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों के उल्लंघन में व्यक्तिगत रूप से संपत्ति का दुरुपयोग किया हो। सामान्य समझ में, एक आपराधिक विश्वासघात तब किया जाएगा जब अभियुक्त न्यास में रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का निर्माण या परिवर्तन करके अपने स्वयं के उपयोग के लिए अपराध करता है। यहां, संपत्ति का अंतरिती और अंतरणकर्ता एक संबंध स्थापित करते हैं जिसमें अंतरणकर्ता संपत्ति का स्वामित्व अपने पास रखता है जिसका अर्थ होगा कि संपत्ति के एक निश्चित अवधि के लिए हस्तांतरण के बाद भी; अंतरणकर्ता का कब्ज़ा या नियंत्रण केवल किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी इच्छा तक ही होगा। यह कहा जा सकता है कि दूसरे व्यक्ति को सीमित अवधि के लिए संपत्ति का हस्तांतरण भी अंतरणकर्ता के स्वामित्व अधिकारों के नुकसान का संकेत नहीं करता है। संपत्ति के न्यास के लिए उनके बीच विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना आवश्यक है। ऐसी श्रेणी से संबंधित मामलों में, आम तौर पर, संपत्ति का कब्ज़ा एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे व्यक्ति को इस वादे के साथ हस्तांतरित किया जाता है कि जब भी मालिक संपत्ति की वापसी चाहेगा, धारक उसे वापस सौंप देगा। यदि अंतरिती, संपत्ति को उसके वास्तविक मालिक को वापस देने के बजाय, उसी का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए करता है या इसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है, तो यह संपत्ति के गबन के सामान माना जाएगा।

14. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के आह्वान का प्रश्न है, सबसे पहले यह उन तत्वों की जांच करना आवश्यक होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक हैं। आसान संदर्भ के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> धारा 420 भा.दं.सं.: धोखा देना और बेईमानी से संपत्ति प्रदान करने के लिए प्रेरित करना।

जो कोई भी धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति प्रदान करने के लिए, या एक मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या हस्ताक्षरित या मुहरबंद किसी भी चीज़ को, और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, प्रेरित करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के सीधे पठन से यह स्पष्ट होता है कि यह धोखाधड़ी और बेईमानी से उस धोखे में डाले गए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने या किसी मूल्यवान प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने या ऐसी किसी भी चीज़ को नष्ट करने, जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, के लिए प्रेरित करने के कृत्य से संबंधित है।

प्रावधान का सीधा पठन यह भी दर्शाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोप का एक आवश्यक तत्व धोखाधड़ी है। इसलिए, धोखाधड़ी की परिभाषा की जाँच करना आवश्यक होगा।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 415 धोखाधड़ी को परिभाषित करती है। त्वरित संदर्भ के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 415 को यहाँ निम्नानुसार उद्धृत किया गया है: -

धारा 415: धोखाधड़ी

जो कोई भी, किसी व्यक्ति को छल करके, कपटपूर्वक या बेईमानी से उस धोखे में डाले गए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या इस बात पर सहमति देने के लिए प्रेरित करता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखेगा, या जानबूझकर धोखे में डाले गए व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने या कार्य न करने के लिए प्रेरित करता है, जो वह उस धोखे में न पड़ने पर नहीं करता या नहीं छोड़ता, और जिसके कार्य या कार्य न करने से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या हानि होती है या होने की संभावना है, उसे धोखाधड़ी करना कहा जाता है।

स्पष्टीकरण

तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के भीतर छल है।

17. **इंदर मोहन गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, एआईआर 2008 एस.सी. 251** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि धारा 420 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, कुछ आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 420, जिसमें धोखाधड़ी और संपत्ति के वितरण को बेईमानी से प्रेरित करना शामिल है, को लागू करने के लिए, अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा किया जाना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में वर्णित "धोखाधड़ी" के आवश्यक तत्व भी इसमें लागू होते हैं, तभी और वहीं से भारतीय दंड संहिता की धारा 420 प्रभावी होती है, इसलिए यहाँ धारा 415 के आवश्यक घटक हैं और वे इस प्रकार हैं:

i. गुमराह करने वाले प्रतिनिधित्व या कोई झूठा प्रतिनिधित्व करके किसी व्यक्ति को छलना, जिसमें बेईमानी से तथ्यों को छिपाना या किसी अन्य कार्य द्वारा या किसी कार्य को न करने के तरीके से भी शामिल है,

ii. बेईमानी और कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को प्रेरित करना और उसे या तो संपत्ति सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाए रखने की सहमति देने से संबंधित विकल्प देना, या उस व्यक्ति को धोखा देने या कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से, जो उसने दूसरे व्यक्ति द्वारा धोखा न दिए जाने पर नहीं किया होता,

iii. इस प्रकार के कार्य न करने और छल करने के कार्य से उस व्यक्ति के शरीर, मन और संपत्ति को हानि और क्षति होने की संभावना है।

इस धारा में दो श्रेणियाँ बताई गई हैं, पहली कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना और दूसरी, धोखा दिए गए व्यक्ति द्वारा किए गए या छोड़े गए कार्य जो वह दूसरे व्यक्ति द्वारा धोखा न दिए जाने पर नहीं करता। इन दोनों के बीच मूल अंतर इरादे के बारे में है। पहली श्रेणी में हम देखते हैं कि यह कपटपूर्ण और बेईमान है और दूसरी श्रेणी में हम देखते हैं कि यह जानबूझकर है लेकिन कपटपूर्ण और बेईमान होना आवश्यक नहीं है। धोखाधड़ी के लिए यह दिखाना आवश्यक होगा कि कपटपूर्ण और बेईमान इरादा रहा है।

18. **एमडी इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2010 एआईआर एस.सी.डब्ल्यू. 405** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक घटकों के बारे में बताया था और उस उद्देश्य के लिए, धोखाधड़ी मुख्य घटक है लेकिन उसी अपराध को गठित करने के लिए एकमात्र नहीं है। धारा 415 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी की उपस्थिति के अलावा इन आगे की बातों का पालन किया जाना चाहिए:

i. किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए धोखा दिए गए व्यक्ति का बेईमानी से उत्प्रेरण होना चाहिए, या

ii. किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या हिस्से को बनाना, बदलना या नष्ट करना और इसमें मुहरबंद और हस्ताक्षरित कुछ भी शामिल है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में भी सक्षम है।

19. **अल्पिक फाइनेंस लिमिटेड बनाम पी. सदाशिवन और अन्य, एआईआर 2001 एस.सी. 1226** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि किसी को धोखा देने का मूल रूप से मतलब किसी को किसी ऐसी चीज़ के बारे में वास्तव में विश्वास दिलाना है जो पहली नज़र में सच लगेगी लेकिन जब ठीक से देखा जाता है तो वह वास्तव में झूठी होती है और जो धोखा दे रहा है वह भी जानता है कि वह चीज़ झूठी है और अपराध करते समय यह बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से भी होना चाहिए।

20. **विजय कुमार घई और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2022) 7 एस.सी.सी. 124** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और धारा 415 के साथ पढ़ी गई भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और धारा 420 के प्रत्येक आवश्यक घटक का विस्तार से अवलोकन किया।

21. दोषपूर्ण इरादा या "अपराधिक मनःस्थिति" धोखाधड़ी के अपराध का आवश्यक घटक है। **हरि प्रसाद चमारिया बनाम बिशुन कुमार सुरेखा और अन्य,** जैसा कि **एआईआर 1974 एस.सी. 30** में रिपोर्ट किया गया है, में यह माना गया था कि जब तक शिकायतकर्ता उस समय बेईमान या कपटपूर्ण इरादा नहीं दिखाता जब

शिकायतकर्ता ने पैसे दिए, तब तक यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध नहीं होगा और यह केवल अनुबंध का उल्लंघन होगा।

22. **हीरा लाल हरि लाल भगवती बनाम सी.बी.आई., एआईआर 2003 एस.सी. 2545** में रिपोर्ट किए गए मामले में, यह अवलोकन किया गया है कि धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करने या लेनदेन में प्रवेश करने या कोई प्रतिनिधित्व करने के समय अभियुक्त का कपटपूर्ण या बेईमान इरादा था।

23. **हरमनप्रीत सिंह आहलूवालिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2009) 7 एस.सी.सी. 712** में रिपोर्ट किए गए मामले में, यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रावधान के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किसी भी कपटपूर्ण या गलत या बेईमान इरादे के घटक और तत्व अनुबंध की बहुत शुरुआत से ही मौजूद होने चाहिए।

24. **ए.एम. मोहन बनाम एस.एच.ओ. और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1716 सन् 2024, दिनांकः 20.03.2024** को तय किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के घटक दिखने चाहिए। विशेष रूप से, इसे यह प्रदर्शित करना चाहिए कि एक व्यक्ति ने किसी को धोखा दिया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति सौंपने के लिए उत्प्रेरित किया है, और यह कि प्रलोभन देने के समय बेईमान इरादा था। बेईमान उत्प्रेरण भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है। यदि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में आवश्यक तत्वों की कमी है, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। वर्तमान मामले में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के आवश्यक तत्व गायब हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी थी।

25. **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अखिल शारदा और अन्य, [2022] 6 एस.सी.आर. 772** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने अवलोकन किया कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत नहीं आता है क्योंकि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों के आवश्यक घटक गायब हैं और वर्तमान मामले के तथ्य भी वही हैं।

26. दोहराव के जोखिम पर, यह दोहराया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में उल्लिखित धोखाधड़ी का एक आवश्यक घटक इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि बेईमान और कपटपूर्ण इरादे का अस्तित्व प्रारंभिक वादे से या लेनदेन की शुरुआत से ही मौजूद होना चाहिए।

27. दोनों प्रावधानों का अवलोकन यह दर्शाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी का अधिक गंभीर रूप है जिसमें संपत्ति सौंपने के उद्देश्य से पीड़ित को उत्प्रेरित करना शामिल है।

28. **जी. सागर सूरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 2000 एस.सी. 754** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र को बहुत सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता को मान्यता दी यदि मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक अपराध का लबादा पहनाया गया है। आपराधिक कार्यवाही कानून में उपलब्ध अन्य उपचारों का शॉर्ट कट नहीं है। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

29. **परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2013) 11 एस.सी.सी. 673** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय न्यायालय ने यह मान्यता दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को विचारशील और सतर्क रहना होगा। इस शक्ति का उपयोग केवल प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसे मामले को देखना होगा और यदि आपराधिक अपराध के घटक गायब हैं और विवाद केवल एक सिविल मामले से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए ताकि कानून की प्रक्रिया और न्यायालय के दुरुपयोग को रोका जा सके।

30. **मितेश कुमार जे. शा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एआईआर 2021 एस.सी. 5298** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि सिविल विवाद की सीमाओं को खींचने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार अनिवार्य रूप से इसे आपराधिक रंग दिया गया है। यह भी निर्धारित किया गया है कि कई उदाहरण थे जहां सिविल विवाद को केवल अपेक्षाकृत त्वरित राहत का लाभ उठाने के लिए आपराधिक रंग दिया गया है। यह अभ्यास कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

31. **रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2021) 14 एस.सी.सी. 626** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए फिर से परमजीत बत्रा (उपरोक्त) का हवाला दिया और उल्लेख किया कि यदि विवाद सिविल प्रकृति का है और उसे आपराधिक अपराध का रंग दिया गया है, तो उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

32. **कपिल अग्रवाल और अन्य बनाम संजय शर्मा और अन्य, एआईआर 2021 एस.सी. 1241** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की कि सिविल प्रकृति के विवादों को आपराधिक रंग देकर विरोधी पक्ष को परेशान करने के हथियार के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रद्द किया जा सकता है।

33. **नरेश कुमार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1510 सन् 2024 (एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 1570 सन् 2021 से उत्पन्न) दिनांक: 12.03.2024** को तय किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से मान्यता दी कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो मूल रूप से सिविल प्रकृति की हैं।

34. अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच वर्तमान मामला केवल सिविल प्रकृति का है लेकिन इसे आपराधिक रंग दिया गया है और यह किसी भी मामले में आपराधिक

अपराध को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी शामिल नहीं थी, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट न तो धोखाधड़ी के और न ही आपराधिक विश्वासघात के घटकों को संतुष्ट या पूरा करती है।

35. मामले के तथ्यों से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता का धोखाधड़ी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और जिसके लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। धोखाधड़ी के आरोप स्पष्ट रूप से अभियोजन के लिए एक अच्छा मामला नहीं बनाते हैं, बल्कि वे प्रकृति में तुच्छ प्रतीत होते हैं, और इसे साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर कोई निर्णायक सबूत नहीं रखा गया है जो वास्तव में धोखाधड़ी के इरादे को दर्शाता हो। यह न्यायालय महसूस करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक घटक सरेआम या प्रत्यक्ष रूप से गायब हैं। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों की प्रकृति की बारीकी से जाँच करने के बाद, यह न्यायालय महसूस करता है कि चुनौती दी गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों की प्रकृति आपराधिक कार्यवाही से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें सिविल प्रकृति का विवाद शामिल है। इस मामले के अनोखे तथ्यों में, यह न्यायालय **नरेश कुमार (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन करना चाहेगा, जिसमें यह अवलोकन किया गया है कि उच्च न्यायालय को उन कार्यवाहियों को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच एक सिविल विवाद प्रतीत होती हैं।

36. ऊपर किए गए विचार-विमर्श के आलोक में, यह न्यायालय महसूस करता है कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप या तो धारा 406 या धारा 420 के तहत अपराध का गठन नहीं करते हैं, और इसलिए उपरोक्त में जाँच जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह न्यायालय इसे उचित और सही मानता है कि पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2016 और इसके अनुसरण में शुरू की गई सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द और अपास्त कर दिया जाए।

37. तदनुसार, आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है और ऊपर उल्लिखित प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, और इसके अनुसरण में की गई सभी आगे की

कार्यवाहियों को एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे एक समापन रिपोर्ट तैयार करें और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें।

38. शिकायतकर्ता उचित मंच पर पहुँचकर अभियुक्तों द्वारा कथित तौर पर किए गए सिविल गलतियों के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

39. स्थगन याचिका का भी निपटारा किया जाता है।

(फरजंद अली), न्यायमूर्ति

3-ममता/

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

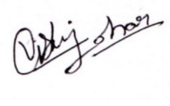

एडवोकेट विष्णु जांगिड़